भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 307

जिसका उत्तर 27 नवंबर, 2024 को दिया जाना है ।

6 अग्रहायण , 1946 (शक)

तमिलनाडू में डिजिटल इंडिया मिशन

307. श्री थरानिवेंथन एम. एस. :
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री मलैयारासन डी.:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2015 में लॉन्च होने के पश्चात से डिजिटल इंडिया मिशन की उपलब्धियां और तमिलनाडू विशेष रूप से अरनी और कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इसकी सेवाओं से लाभान्वित नागरिकों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और ई-गवर्नेंस सेवाओं सहित डिजिटल इंडिया की अवसंरचना की वर्तमान स्थिति और शुरू की गई प्रमुख पहलें क्या हैं;

(ग) विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड की चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की प्रभावशीलता और प्रभाव संबंधी कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडू में डिजिटल इंडिया मिशन के विभिन्न घटकों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ-साथ अब तक उपयोग की गई आवंटित निधियाँ क्या है; और

(च) क्या सरकार की आने वाले वर्षों में मिशन का दायरा बढ़ाने या विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख विज़न क्षेत्रों, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढाँचा, मांग पर शासन और सेवाएँ, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण पर केंद्रित है। समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाएँ, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें, और भारत में निवेश और रोज़गार के अवसर और डिजिटल तकनीकी क्षमताएँ बनाएँ।

डिजिटल इंडिया ने सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है और सरकार और शासन पर भरोसा बढ़ाया है। इसने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लाभार्थियों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करने में भी मदद की है।

तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और उन्हें डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनाएं/परियोजनाएं

कार्यान्वित की जा रही हैं।

तमिलनाडु राज्य में ऐसी डिजिटल सुविधाओं में निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

क) लगभग 19,934 सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) कार्यरत हैं।
ख) कार्यात्मक डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत 10.55 लाख व्यक्तियों का प्रमाणीकरण।

तमिलनाडु राज्य में जिलावार कार्यात्मक सीएससी और पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करने, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार करने के लिए कई योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। डिजिटल इंडिया के तहत कुछ प्रमुख पहलों का विवरण अनुबंध -III में दिया गया है।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के नागरिकों को विभिन्न पहलों, जैसे कि नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजीलॉकर, ई-साइन, ई-अस्पताल, ई- संजीवनी, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), माईस्कीम और माईगव आदि के तहत ई-सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाया गया है ।

(ग): ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल साक्षरता, कौशल और जागरूकता को बढ़ावा देने तथा किफायती इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) (वर्ष 2014 से 2016 के दौरान, भारत सरकार ने आम जनता को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए दो योजनाएं "राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)" और "डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)" लागू की थीं, जिसका ग्रामीण भारत सहित पूरे देश में संचयी लक्ष्य 52.50 लाख व्यक्ति (प्रत्येक पात्र परिवार से एक व्यक्ति) था। इन दोनों योजनाओं के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से लगभग 42% उम्मीदवार ग्रामीण भारत से थे। दोनों योजनाएं अब बंद हो चुकी हैं।

(ii) वर्ष 2017 में, सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना को मंजूरी दी थी, जिसका लक्ष्य देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करना था। 31 मार्च 2024 तक ' 6 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के कुल लक्ष्य की तुलना में 7.35 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 6.39 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.78 करोड़ उम्मीदवारों को देश भर में पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया। पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर दिनांक 31.03.2024 को संपन्न हो गया है।

(iii) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नैसकॉम के साथ मिलकर फ्यूचर स्किल्स प्राइम नामक कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों जिसमें संवर्धित/आभासी वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग/3डी प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल और मोबाइल, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन शामिल हैं में आईटी पेशेवरों को पुनः कौशल प्रदान करना/कौशक उन्नयन करना है।

(iv) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

(एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इस कौशल प्रमाणन योजना का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद करेगा। 26 जुलाई 2024 तक, लगभग 19.31 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 9.44 लाख उम्मीदवारों को पीएमकेवीवाई योजना के तहत प्रमाणित किया गया है।

(v) डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और देश भर में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुविधा के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म लागू किया गया है। यह प्लेटफॉर्म निःशुल्क है और इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। आज तक दीक्षा का उपयोग करके 557.09 करोड़ शिक्षण सत्र प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें 17.98 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 14.38 करोड़ पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए हैं। आज तक दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 1.75 करोड़ उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं।

(vi) देश में बुनियादी संचार/इंटरनेट कनेक्टिविटी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड वायर लाइन कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है। सितंबर 2024 तक दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार गांवों का डेटा), लगभग 6,22,840 गांव (2जी/3जी/4जी) कनेक्टिविटी से कवर किए गए हैं और 6,14,564 गांव 4जी तकनीक से कवर किए गए हैं।

(vii) भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है, और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। दिनांक 04.08.2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,64,554 जीपी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है, जिसमें मौजूदा जीपी भी शामिल हैं जो पहले से ही सेवा के लिए तैयार हैं। अक्टूबर, 2024 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,283 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

(viii) भारत सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए एक पुनः डिज़ाइन और विस्तारित योजना शुरू की है, जिसका नाम है "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23"। पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग-V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के लिए कुल 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इस निधि का उपयोग वर्तमान में कवर की गई ग्राम पंचायतों से लेकर गांवों तक भारतनेट का विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, ताकि सरकारी संस्थानों (जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुलिस स्टेशन, कृषि विकास केंद्र, डाकघर, राशन की दुकान आदि), निजी संस्थानों और घरों को भारतनेट नेटवर्क से ओएफसी पर अंतिम मील कनेक्टिविटी (एलएमसी) मिल सके।

(घ): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सभी प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन आम तौर पर एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के माध्यम से किया जाता है, जो निष्पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं होता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अक्टूबर, 2020 में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स (सीआईपीएस), हैदराबाद के माध्यम से आयोजित किए गए थे। अध्ययन से पता चला है कि डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित सूचना तक पहुँच प्रदान करके नागरिक सेवाओं को बदल रहा है, सरकार और नागरिकों के बीच विभिन्न प्रणालियों और सेवाओं को एकीकृत कर रहा है, जिससे नागरिकों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मूल्यों को सशक्त और बढ़ाया जा रहा है।

(ड़): डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजन शामिल है । प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता होती है और तदनुसार कार्यान्वयन मंत्रालय/विभागों द्वारा परियोजना-की आयोजन तैयार की गई है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बजट विवरण बनाए रखा जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 8 उप-योजनाएँ हैं। ये उप-योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ हैं, कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा आबंटित और उपयोग किया गया बजट निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**व्यय** **(**करोड़ रु में**)**
2015-2016	1384.50
2016-2017	1176.38
2017-2018	1451.59
2018-2019	3328.54
2019-2020	3191.09
2020-2021	3030.54
2021-2022	4504.36
2022-2023	3863.13
2023-2024	4174.14
2024-2025	2829.38 (18/11/2024 की स्थिति के अनुसार)

(च) अगस्त 2023 में, सरकार ने 15वें वित्त आयोग यानी वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,903.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार/विस्तारण को मंजूरी दी।

****

अनुबंध- I

तमिलनाडु राज्य में जिलेवार क्रियाशील सीएससी

क्रम सं.	**जिलों के नाम**	**सक्रिय सीएससी**
1	अरियालुर	372
2	चेंगलपट्टू	267
3	चेन्नई	592
4	कोयंबटूर	690
5	कुड्डालोर	859
6	धर्मपुरी	598
7	डिंडीगुल	547
8	इरोड	596
9	कल्लाकुरिची	389
10	कांचीपुरम	385
11	कन्याकुमारी	836
12	करूर	346
13	कृष्णागिरी	600
14	मदुरै	613
15	माइलादुत्रयी	121
16	नागपट्टिनम	426
17	नमक्कल	376
18	पेरम्बलुर	315
19	पुदुक्कोट्टई	407
20	रामनाथपुरम	670
21	रानीपेट	250
22	सलेम	1041
23	शिवगंगा	453
24	तेनकासी	456
25	तंजावुर	644
26	नीलगिरी	196
27	थेनी	480
28	तिरुवल्लुर	540
29	थिरुवरुर	372
30	तिरुचिरापल्ली	829
31	तिरुनेलवेली	688
32	तिरुपथुर	268
33	तिरुपूर	516
34	तिरुवन्नामलाई*	695
35	तूतीकोरिन	581
36	वेल्लोर	482
37	विल्लुपुरम	650
38	विरुधुनगर	788
	कुल	**19,934**

*** इसमें** अरणी निर्वाचन क्षेत्र **शामिल है**

अनुबंध- II

पीएमजीदिशा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य की जिलेवार स्थिति:

क्रम सं .	**जिलों के नाम**	**पंजीकृत अभ्यर्थी**	**प्रशिक्षित अभ्यर्थी**	**प्रमाणित अभ्यर्थी**
1.	अरियालुर	64,156	57,289	41,521
2.	चेन्नई	240	159	122
3.	कोयंबटूर	47,814	35,754	25,026
4.	कुड्डालोर	41,012	28,758	19,064
5.	धर्मपुरी	77,289	64,813	49,392
6.	डिंडीगुल	40,951	33,980	23,524
7.	इरोड	42,479	35,604	28,212
8.	कांचीपुरम	38,116	26,204	19,207
9.	कन्याकुमारी	30,580	23,710	17,379
10.	करूर	41,929	36,663	25,691
11।	कृष्णागिरी	71,346	63,430	48,405
12.	मदुरै	21,776	15,226	9,729
13.	नागपट्टिनम	36,584	26,814	17,858
14.	नमक्कल	43,372	35,812	28,058
15.	पेरम्बलुर	47,162	43,402	30,964
16.	पुदुक्कोट्टई	92,548	81,623	61,284
17.	रामनाथपुरम	38,405	27,702	19,382
18.	सलेम	80,404	73,193	58,153
19.	शिवगंगा	72,036	58,065	48,961
20.	तंजावुर	61,175	52,646	34,869
21.	नीलगिरी	6,625	2,202	1,446
22.	थेनी	20,819	14,783	10,195
23.	तिरुवल्लुर	56,489	48,445	32,073
24.	थिरुवरुर	48,957	35,015	23,866
25.	तिरुचिरापल्ली	1,08,842	95,369	72,025
26.	तिरुनेलवेली	50,015	38,889	27,719
27.	तिरुपूर	31,576	25,148	18,399
28.	तिरुवन्नामलाई*	1,62,506	1,50,730	1,34,955
29.	तूतीकोरिन	15,992	10,782	6,900
30.	वेल्लोर	47,167	32,172	22,856
31.	विल्लुपुरम**	1,14,547	95,151	70,931
32.	विरुधुनगर	51,628	38,347	27,069
	कुल	**17,04,537**	**14,07,880**	**10,55,235**

*** इसमें** अरणी निर्वाचन क्षेत्र **शामिल है**

** इसमें कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र **शामिल है**

अनुबंध- III

देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल साक्षरता और ई-गवर्नेंस सेवाओं में सुधार करने, इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत किए गए कुछ प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:

- **इंटरनेट कनेक्टिविटी : देश में** बुनियादी संचार/इंटरनेट कनेक्टिविटी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा वायरलेस मोबाइल और फिक्स्ड वायर लाइन कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सितंबर 2024 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, देश के 6,44,131 गांवों में से (भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार गांवों का डेटा), लगभग 6,22,840 गांवों को (2जी/3जी/4जी) कनेक्टिविटी के साथ कवर किया गया है और 6,14,564 गांवों को 4जी तकनीक के साथ शामिल किया गया है।

- **भारतनेट:** भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, ताकि आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है, जो सेवा प्रदाताओं के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुलभ है, और इसका उपयोग वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज्ड लाइन, डार्क फाइबर, मोबाइल टावरों के लिए बैकहॉल आदि जैसी ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। दिनांक 04.08.2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,64,554 जीपी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दी है, जिसमें मौजूदा जीपी भी शामिल हैं जो पहले से ही सेवा के लिए तैयार हैं। अक्टूबर-2024 तक देश में भारतनेट परियोजना के तहत 2,14,283 जीपी को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क :** राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क ('एनकेएन') राष्ट्रीय/राज्य डेटा केंद्रों (एनडीसी/एसडीसी), राज्य-व्यापी क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) का डिजिटल-ट्रैफ़िक वहन करता है और विभिन्न डिजिटल इंडिया पहलों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह विभिन्न जी2जी (सरकार से सरकार) और जी2सी (सरकार से नागरिक) सेवाओं का डिजिटल-ट्रैफ़िक भी वहन करता है। एनकेएन संसाधनों और सहयोगी अनुसंधान को साझा करने को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च गति वाले डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ता है। अब तक, 2024 तक, एनकेएन के तहत संस्थानों के लिए 1,802 लिंक चालू किए जा चुके हैं और प्रचालनरत हैं । पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों को 522 एनकेएन लिंक से जोड़ा गया है।

- **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम):** वर्ष 2014 से 2016 के दौरान, भारत सरकार ने लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए दो योजनाएं, "राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम)" और "डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा)" लागू की थीं। इनका लक्ष्य ग्रामीण भारत सहित पूरे देश में 52.50 लाख लोगों (प्रत्येक पात्र परिवार से एक व्यक्ति) को प्रशिक्षित करना था। इन दोनों योजनाओं के तहत कुल 53.67 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से लगभग 42% उम्मीदवार ग्रामीण भारत से थे। दोनों योजनाएं अब बंद हो चुकी हैं।

- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** डिजिटल साक्षरता दर में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, भारत सरकार ने देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करके ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक योजना लागू की। 31 मार्च 2024 तक ' 6 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के कुल लक्ष्य की तुलना में, 7.35 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया गया और 6.39 करोड़ को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से

4.78 करोड़ उम्मीदवारों को देश भर में पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रमाणित किया गया। पीएमजीदिशा योजना के तहत प्रशिक्षण और प्रमाणन आधिकारिक तौर पर 31.03.2024 को संपन्न हो गया है।

- **आधार :** आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है जो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है; जिसे कभी भी, कहीं से भी प्रमाणित किया जा सकता है और यह डुप्लिकेट और नकली पहचान को भी समाप्त करता है। आज तक, 138.64 करोड़ आधार संख्याएँ बनाई जा चुकी हैं।

- **सामान्य सेवा केंद्र-** सीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के माध्यम से डिजिटल मोड में सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और आधार से संबंधित सेवाएं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान शामिल हैं। अब तक देश भर में (ग्रामीण + शहरी) 5.91 लाख सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 4.69 लाख सीएससी ग्राम पंचायत (ग्रामीण) स्तर पर कार्यरत हैं।

- **डिजिलॉकर** : यह दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने और सत्यापित करने का एक मंच है। इसने 34.95 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान की है और 776 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज़ उपलब्ध कराए हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली कई फिनटेक कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को आसानी से जोड़ने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग कर रही हैं।

- **नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप** (उमंग): उमंग सभी भारतीय नागरिकों के लिए एकीकृत मंच है, जिससे वे केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक अखिल भारतीय ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। वर्तमान में, 207 केंद्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों की 2,057 सेवाएँ उमंग पर उपलब्ध हैं।

- **माईस्कीम :** माईस्कीम एक राष्ट्रीय मंच है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। यह मंच नागरिकों को उनके लिए सही सरकारी योजनाएँ खोजने में मदद करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। अब तक कुल 2,770 योजनाएँ प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से केंद्र सरकार की योजनाएँ 520 हैं जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाएँ 2,230 हैं।

- **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई):** यह भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। अकेले अक्टूबर, 2024 के महीने में यूपीआई का उपयोग करके 1,658 करोड़ से अधिक वित्तीय लेनदेन किए गए। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तकनीक और डिवाइस को अलग-अलग बनाकर, यूपीआई ने जमीनी स्तर तक वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा)** : यह दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विविध स्कूली शिक्षा मंच है। 22 जुलाई 2024 तक ' दीक्षा का उपयोग करके 556.37 करोड़ शिक्षण सत्र प्रदान किए गए हैं। इसने 17.95 करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 14.37 करोड़ पाठ्यक्रम पूरे किए हैं।

- **ई-हस्ताक्षर:** ई-हस्ताक्षर सेवा नागरिकों को कानूनी रूप से स्वीकार्य फॉर्म/दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने की सुविधा देती है। यूआईडीएआई की ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का

उपयोग करके विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा इन सेवाओं का लाभ उठाया जा रहा है। सभी ईएसपी द्वारा 79.84 करोड़ से अधिक ई-हस्ताक्षर जारी किए गए हैं।

- **माईगव-** यह एक नागरिक सहभागिता मंच है जिसे सहभागी शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान में, 2.76+ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता माईगव के साथ पंजीकृत हैं, जो माईगव प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं।

- **मेरी पहचान -** नागरिकों को सरकारी पोर्टल तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए जुलाई 2022 में मेरी पहचान नामक राष्ट्रीय एकल साइन-ऑन (एनएसएसओ) प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों की 12,068 सेवाओं को एनएसएसओ के साथ एकीकृत किया गया है ।

- **ई-अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) -** ई-अस्पताल एप्लीकेशन अस्पतालों के आंतरिक कार्यप्रवाह और प्रक्रियाओं के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। वर्तमान में, 694 अस्पतालों को ई-हॉस्पिटल पर शामिल किया गया है और देश भर में 720 अस्पतालों ने ओआरएस को अपनाया है और ओआरएस से 74 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट बुक किए गए हैं।

- **ई-संजीवनी -** भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य समानता की दिशा में एक कदम है। ई-संजीवनी आपके स्मार्टफ़ोन से डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों तक त्वरित और आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करती है। 16,360+ हब और 660 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से 129,200 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (स्पोक के रूप में) पर 30.87 करोड़ से अधिक रोगियों को टेलीमेडिसिन चिकित्सकों के रूप में 225,000 से अधिक डॉक्टरों, चिकित्सा विशेषज्ञों, सुपर-स्पेशलिस्ट और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

- **को-विन-** यह कोविड-19 के लिए पंजीकरण, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और टीकाकरण प्रमाणपत्रों के प्रबंधन के लिए एक खुला मंच है। इसने 110 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया है और 220 करोड़ लोगों को टीकाकरण की खुराक देने में मदद की है।

- **जीवन प्रमाण :** जीवन प्रमाण का उद्देश्य पेंशनभोगी के लिए जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को अब वितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2014 से अब तक 960.88 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र संसाधित किए जा चुके हैं।

- **ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म** - डेटा साझा करने की सुविधा और गैर-व्यक्तिगत डेटा पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया गया है। 12,434+ कैटलॉग में 5.04 लाख से अधिक डेटासेट प्रकाशित किए गए हैं। प्लेटफ़ॉर्म ने 104.90 लाख डाउनलोड की सुविधा प्रदान की है।

******